LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, December 18, 2024 / Agrahayana 27, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 18, 2024 / Agrahayana 27, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

… 1

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 2 – 50
(S.Q. NO. 321 – 340)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 3681 – 3910)

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, December 18, 2024 / Agrahayana 27, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, December 18, 2024 / Agrahayana 27, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 89

COMMITTEE ON ESTIMATES 290
1st to 5th Reports

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 291
1st to 8th Reports

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS 292
Statements

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 293
Statements

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 294
1st to 5th Reports

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT 295
1st to 4th Reports

STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 2744 DATED 07.08.2024 RE: (I) 'RESEARCH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY' AND (II) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWER - LAID 295
Dr. Jitendra Singh

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 27TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY– LAID 296

Shri Shripad Yesso Naik

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 47TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID 296

Dr. L. Murugan

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 297 - 310

Shri Anurag Sharma 297

Shri Praveen Patel 298

Shri Mukesh Rajput 298

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 298

Shri Darshan Singh Choudhary 299

Shri Arun Kumar Sagar 299

Shri Jai Prakash 300

Dr. Sanjay Jaiswal 300

Shri Ashok Kumar Rawat 301

Shrimati Bharti Pardhi 301

Shri Vijay Kumar Dubey 302

Shri Bhartruhari Mahtab 302

Dr. Bachhav Shobha Dinesh 303

Dr. Prashant Yadaorao Padole 303

Dr. Amar Singh 304

Shri Robert Bruce C. 304

Shri Kodikunnil Suresh 305

Shri Rajeev Rai 305

Shri Dharmendra Yadav **306**

Prof. Sougata Ray **307**

Shri T.M. Selvaganapathi **307**

Shrimati Kanimozhi Karunanidhi **308**

Shrimati Lovely Anand **309**

Shri Sudama Prasad **309**

Shri K. Radhakrishnan **310**

Shri Rajesh Ranjan **310**

xxx

(1100/MM/SNT)

1100बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न 321।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया प्रश्न काल में सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। … (व्यवधान) जब बाबा साहब जिंदा थे, तो उनका तिरस्कार किया। … (व्यवधान) इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब की फोटो लगाने से भी मना कर दिया था।… (व्यवधान) बाबा साहब को दो बार लोक सभा का चुनाव हराया।… (व्यवधान)

1101 बजे

(इस समय श्री शफी परम्बिल, श्री बैन्नी बहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं।… (व्यवधान) हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं।… (व्यवधान) राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री जी ने संविधान की 75 वर्ष की यात्रा पर जो भाषण दिया था, वह उस हाउस की बात है।… (व्यवधान) लेकिन ये लोग इस सदन में बाबा साहब का चित्र लेकर आ रहे हैं। … (व्यवधान) बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हो गयी है, क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहब के पांच तीर्थ स्थान बनाए हैं।… (व्यवधान) बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है।… (व्यवधान) लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं।… (व्यवधान) बाबा साहब के प्रति इनमें कोई सम्मान नहीं है।… (व्यवधान) बाबा साहब को दो-दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी, आज ये ढोंग कर रही है।… (व्यवधान) आज ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है।… (व्यवधान) सवाल ये है कि इन लोगों ने बाबा साहब को संसद में नहीं आने दिया और अब ये पार्टी ढोंग कर रही है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

1102 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/KDS/AK)

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri P.C. Mohan *in the Chair*)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

1400 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, a few notices of Adjournment Motion have been received on different subjects. Hon. Speaker has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

1401 hours

(At this stage, Prof. Varsha Eknath Gaikwad and some other hon. Members came and stood near the Table)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद, नई दिल्ली के 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) भौतिकी संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री जयंत चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 2023-2024 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही के अंत में बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सरकार के दायित्वों को पूरा करने में हुए विचलन का वर्णन करने वाला विवरण।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री रामदास अठावले जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI V. SOMANNA): I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gati Shakti Vishwavidyalaya, Vadodara, for the year 2022-2023.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 199 of the Railways Act, 1989:-

(i) The Member (Selection and Appointment) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 755(E) in Gazette of

India dated 9th December, 2024.

(ii) The Independent Member (Selection and Appointment) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 756(E) in Gazette of India dated 9th December, 2024.

(iii) The Vice Chairperson (Selection and Appointment) Amendment Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 757(E) in Gazette of India dated 9th December, 2024.

… (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2023-2024.

… (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री सतीश चंद्र दुबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4561(अ) जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा "श्रेणी 'क' अन्वेषण एजेंसियों" के अंतर्गत मेसर्स एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 5066(अ) जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा "श्रेणी 'क' अन्वेषण एजेंसियों" के अंतर्गत मेसर्स एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वरदान एनवायरनेट एलएलपी को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 5069(अ) जो दिनांक 26 नवंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा "श्रेणी 'क' अन्वेषण एजेंसियों" के अंतर्गत सिनर्जी जियोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(7) अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4819(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि इसमें उल्लिखित सीमा बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ अपतटीय क्षेत्र के भाग समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे।

(दो) का.आ. 4760(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की प्रथम अनुसूची में, उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, श्री सुकान्त मजूमदार जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड , शिलांग का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

प्राक्कलन समिति
पहला से पांचवां प्रतिवेदन

1404 बजे

डॉ. राजकुमार सांगवान : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** प्रस्तुत करता हूं**:-**

(1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'सोलर पार्कों का विकास और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन – एक समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत हरित राजमार्ग सहित विभिन्न परियोजनाओं का आंकलन' विषय के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति' विषय के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्रा) पार्क योजना के माध्यम से सशक्तिकरण तथा रुग्ण वस्त्र इकाइयों/पीएसयू (बीआईसी, एनटीसी, सीटीएल आदि) के पुनरूद्धार के प्रयास' विषय के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(1405/UB/YSH)

HON. CHAIRPERSON: Shri Baijayant Panda – Not present.

Shri Tariq Anwar.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

1ST to 8TH Reports

SHRI TARIQ ANWAR (KATIHAR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings (Eighteenth Lok Sabha):-

(1) First Report on the subject 'Procurement of hardware/ software item to the tune of Rs. 890.34 Crores through strategic alliance relating to National Informatics Centre Services Inc. (NICSI)' based on Audit Para No. 6.1 of Report No. 03 of 2021.

(2) Second Report on the subject 'Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)'.

(3) Third Report on the subject 'Undue enrichment through Recovery of Turnover Tax from consumer' relating to Indian Oil Corporation Limited (IOCL) based on Audit Para No. 2.1 of Report No.14 of 2021.

(4) Fourth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Eighteenth Report (17th Lok Sabha) on 'NMDC Limited' based on C&AG Report No. 5 of 2019 relating to Operational Performance of NMDC Ltd.

(5) Fifth Report on the subject 'Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC)'.

(6) Sixth Report on the subject 'Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)'.

(7) Seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-second Report (17th Lok Sabha) on 'Unfruitful Expenditure Towards Construction of Copper Ore Tailings Beneficiation Plant relating to Hindustan Copper Limited (HCL)' based on Audit Para No. 6.1 of C&AG Report No. 14 of 2021.

(8) Eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Twenty-first Report (17th Lok Sabha) on 'Oil India Ltd (OIL)'.

… (*Interruptions*)

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
Statements

SHRI TARIQ ANWAR (KATIHAR): Sir, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by Government on the Observations/Recommendations contained in the Action Taken Reports of the Committee on Public Undertakings:-

(1) 16th Report (17th Lok Sabha) of CoPU on Action Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in 9th Report (17th Lok Sabha) on 'Loss due to Imprudent Underwriting and lack of proper risk assessment relating to New India Assurance Company Limited (NIACL) [Based on Para no. 3.2 of C&AG Report no. 13 of 2019]'.

(2) 20th Report (17th Lok Sabha) of CoPU on Action Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in 17th Report (17th Lok Sabha) on 'Avoidable loss due to extension of loan in terminated projects relating to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) [Based on Para No. 5.2 of CAG Report No. 18 of 2020]'.

(3) 23rd Report (17th Lok Sabha) of CoPU on Action Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in 19th Report (17th Lok Sabha) on 'Review of Loans to Road Projects relating to India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) [Based on Para No. 5.1 of C&AG Report No. 18 of 2020]'.

… (*Interruptions*)

लोक लेखा समिति
विवरण

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की कार्य-निष्पादन संपरीक्षा' के बारे में लोक लेखा समिति के 38वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) 'प्राथमिक शिक्षा को पोषणात्मक सहयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)' के बारे में लोक लेखा समिति के 9वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) 'आधिक्य भुगतान में परिणत होने वाले दावों की लापरवाहीपूर्ण संवीक्षा' के बारे में लोक लेखा समिति के 41वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 73वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(4) 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)' के बारे में 55वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(5) 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणी को समय से प्रस्तुत किए जाने में मंत्रालयों द्वारा गैर-अनुपालन' के बारे में पहले प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 56वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(6) 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(7) 'इंदिरा आवास योजना' के बारे में 43वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(8) "सेंटर बफर कपलर (सीबीसी) घटकों की विफलता के कारण ट्रेन पार्टिंग के लिए हानि" के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 80वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(9) 'भारतीय रेल में खाली भूमि का प्रबंधन' के बारे में समिति के 93वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 108वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(10) 'विनियंत्रित फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति' के बारे में 65वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 111वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(11) 'रक्षा संपदा प्रबंधन' के बारे में समिति के 89वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 113वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

… (<u>व्यवधान</u>)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
पहला से पांचवा प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** प्रस्तुत करता हूँ**:-**

(1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग – पहल और चुनौतियां (2023-24)' के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(5) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

… (<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: Item no. 19. Shri Asaduddin Owaisi – Not present.

Item no. 20. Shri Godam Nagesh.

… (Interruptions)

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
1ST to 4TH Reports

SHRI GODAM NAGESH (ADILABAD): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2024-25):-

(1) First Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2024-25) (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment).

(2) Second Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2024-25) (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities).

(3) Third Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2024-25) (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Tribal Affairs.

(4) Fourth Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (2024-25) (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Minority Affairs.

… (*Interruptions*)

STATEMENT CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 2744 DATED 07.08.2024
RE: (i) RESEARCH IN SCIENCE AND TECHNOLOGY AND (ii) GIVING REASONS FOR DELAY IN CORRECTING THE ANSWER- LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement (i) correcting the reply given on 07.08.2024 to Unstarred Question No. 2744 asked by Shri Rajesh Verma, MP regarding 'Research in Science and Technology' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 27TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Energy on 'Evaluation of Wind Energy in India' pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 47TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 47th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on 'Review of Functioning of Central Board of Film Certification (CBFC)' pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

… (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377 - LAID

1408 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Need to convert outreach programmes for registration of eligible persons with disabilities under Niramaya Scheme in Bundelkhand and Jhansi, Uttar Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): I wish to bring to the attention of this august House the critical need to raise awareness and expand the reach of the Niramaya Scheme for persons with disabilities in the Bundelkhand region. Under this scheme, individuals with disabilities, including those suffering from autism, cerebral palsy, mental retardation, and multiple disabilities, are entitled to health insurance coverage of up to ₹1 lakh. The scheme also provides essential benefits such as OPD Treatment which covers, medicines, diagnostic tests, and pathology, dental care, non-surgical and inpatient care, therapies to reduce the impact of disabilities, transportation expenses for medical purposes etc. However, many eligible beneficiaries in Bundelkhand, particularly in rural areas of Jhansi, are unable to avail these benefits due to lack of awareness and access to valid disability certificates or UDID cards, which are mandatory for enrolment. I urge the Government to conduct focused outreach programs in Bundelkhand and Jhansi to ensure that all eligible persons are registered and receive the benefits of this scheme. I request the establishment of accessible facilitation centres for issuing disability certificates and UDID cards in remote areas. This step will ensure the marginalized sections of society in Bundelkhand can lead dignified lives with adequate healthcare support.

(ends)

Re: Need to set up SAI Centers and educational institutions in Phulpur Parliamentary Constituency

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : मैं लोकसभा फूलपुर से चुनकर आया हूँ। यहाँ प्रयागराज में केंद्रीय विद्यालय होने के नाते शिक्षा को लेकर एक बड़ा माहात्म्य है और साथ ही यहाँ के युवाओं में देश के प्रति कुछ बेहतर करने की जिजीविषा भी है। मेरे प्रधानमंत्री जी द्वारा खेलों इंडिया और फिट इंडिया जैसे मुहिम को जनता का काफ़ी बल मिला और तब से लोगो में इसके प्रति एक अलग ही जागरूकता का प्रकाश फैला है। इसी क्रम में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है मेरे लोकसभा क्षेत्र फूलपुर (उत्तर प्रदेश) में साई केंद्र और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने की कृपा करे। इससे मेरे क्षेत्र के युवाओ को बेहतर भविष्य की ना केवल जीव मिलेगी बल्कि करियर में काफ़ी विकल्प उपलबद्ध होगें साथ ही उक्त मुहिम को साकार करने में काफ़ी बल मिलेगा।

(इति)

Re: Need to establish a new Kendriya Vidyalaya in Farrukhabad Parliamentary Constituency

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक अन्य केन्द्रीय विद्यालय प्रस्तावित है| जिसकी भूमि भी फर्रुखाबाद शहर से मात्र चार किमी दूर पिपरगाँव में चयनित हो चुकी है| परन्तु अभी तक प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली है| अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय के नव निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करनें की कृपा करें| जिससे कि मेरे क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को एक अन्य केन्द्रीय विद्यालय की कमी महसूस न हो।

(इति)

Re: Need to set up Healthcare and Welfare Centres for elderly people in the country

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : विगत 70 वर्षों के दौरान 60 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों की संख्या बढ़कर तीन गुना हो गई है। उनमें से अधिकांश समाज के बदलते परिदृश्य के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था में नहीं है। वह अलग घरों में अकेले रहने के लिए विवश है जो बहुत ही खतरनाक है। व्यावसायिक कर्तव्यों के कारण उनके बच्चे अन्य कस्बों और शहरों तथा कभी-कभी विदेश में रहते हैं। इसके परिणामस्वरुप वृद्ध व्यक्ति उचित चिकित्सा परिचर्या और मदद प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञतायुक्त चिकित्सा केंद्रों की आवश्यकता है जिनमे चिकित्सीय रूप से प्रशिक्षित व्यावसायियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार को पूरे देश में वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वयोवृद्ध व्यक्तियों की देखभाल की जानी चाहिए। देश के प्रत्येक तालुका में इन व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए वयोवृद्ध व्यक्ति कल्याणगृह स्थापित किए जाने चाहिए और इन गृहों के संचालन हेतु समर्पित स्वयंसेवियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं सरकार से एक व्यापक नीति के कार्यान्वयन हेतु पहल करने का आग्रह करता हूं। (इति)

Re: Need to accord the status of 'Jeevant Nadi' to Narmada River

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : भारत सरकार नर्मदा नदी को एक जीवित इकाई मानते हुए जीवंत नदी का दर्जा देती है,तो इसके संरक्षण की जवाबदेही समाज और सरकार दोनों की होगी। जिससे नर्मदा मैया में प्रदूषण कम होगा तटों के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। नर्मदा मैया के किनारे पेड़ काटने, रेत उत्खनन करने व प्रदूषण करने पर जुर्माना तय होगा। नर्मदा तटों पर पौधारोपण होगा, नर्मदांचल लोक बनेगा, सौंदर्य कारण होगा, घाटों का जीर्णोद्धार होगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जो पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के प्रबंधन में मदद करेगा। जिससे 1. जल प्रदूषण कम होगा। 2. मिट्टी का क्षरण रोकेगा। 3. जलवायु परिवर्तन को कम करेगा। 4. जैव विविधता को बढ़ावा देगा। 5. स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। 6. शहरों के गंदे नालों का प्रदूषित पानी बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा मैया में नहीं जाएगा। भारत सरकार की जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं जीव संरक्षण से संबंधित योजनाएं नर्मदा मैया एवं उनकी सहायक नदियों को जीवंत रखने का कार्य करेगी।

(इति)

Re: Need to investigate water pollution caused by power plant, fertilizer and sugar factories in Shahajahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान संसदीय क्षेत्र में स्थित रोजा पावर प्लांट, कृभको फटिलाईजर्स लि०, अवध शुगर एंड एनर्जी लि०. बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि० और डालमिया भारत शुगर एंड इण्डस्ट्रीज लि० के विरूद्ध निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इन संयंत्रों के द्वारा भारी पैमाने पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और इसके प्रदूषित जल से बड़ी दुर्गंध होने के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण हो रहा है तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अस्थमा, फेफड़े. हृदय रोग संबंधी गंभीर बीमारियां भी पनप रही हैं तथा प्रदूषित पानी से किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही हैं।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के हित में जो श्रम कानून बनाए हैं। उनका भी मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त संयंत्रों द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है।

मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित उपरोक्त संयंत्रों के विरूद्ध पर्यावरण को प्रदूषित किए जाने और श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को विस्तारपूर्वक अनेक पत्र लिखे हैं। लेकिन, इन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) में स्थित उपरोक्त सभी संयंत्रों के विरूद्ध केन्द्रीय मंत्रालय स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके जांच करवाई जाए और जांचोपरांत की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। (इति)

Re: Need to run a direct train between Hardoi Railway Station and Ringas Junction Railway Station

श्री जय प्रकाश (हरदोई) : मैं आपके माध्यम से इस सदन में माननीय रेल मंत्रीजी से मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई के अंतर्गत, उत्तर रेलवे के अधीन, हरदोई रेलवे स्टेशन से राजस्थान के सीकर जनपद में, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत रींगस जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए यात्री गाड़ियों के संचालन के लिए अनुरोध करता हूँ। चूंकि रींगस जंक्शन रेलवे स्टेशन खाटूश्याम तीर्थ स्थल का सबसे निकटतम रेलवे जंक्शन है, जहाँ सम्पूर्ण भारत के हर कोने से प्रतिदिन लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री खाटूश्यामजी के दर्शनों के लिए भ्रमण करते हैं। इसी क्रम में, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हरदोई रेलवे स्टेशन से रींगस जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए कोई सीधी यात्रा रेलगाड़ी न होने के कारण हरदोई के हजारों भक्तों. खासकर महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को, रींगस पहुँचने के लिए दो-तीन रेल मार्ग बदलने पड़ते हैं जिससे उन्हें अनेक कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है। अतः मैं मा० रेल मंत्रीजी से अनुरोध करता हूँ कि वे हरदोई रेलवे स्टेशन से रींगस जंक्शन रेलवे स्टेशन को सीधे जोड़ने के लिए यात्री गाड़ियों का संचालन किये जाने के लिए अपनी संस्तुति प्रदान करनें की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to strengthen embankments along Gandak River in Bihar

DR. SANJAY JAISWAL (PASCHIM CHAMPARAN): I draw attention to the recurring floods in North Bihar caused by heavy water discharge from the Valmikinagar barrage on the Gandak river. In 2023, this led to severe damage in West Champaran, inundating fields and settlements. I urge the Government to expedite the strengthening of embankments along the Gandak river to mitigate flood risks and ensure timely relief for affected farmers.

(ends)

Re: Need to declare and develop Bilgram-Mallawan road in Uttar Pradesh as a National Highway

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत बिलग्राम- मल्लावां उन्नाव एक स्टेट हाईवे (संख्या 38) है। यह हरदोई जिला होते हुए एक तरफ जिला उन्नाव और दूसरी तरफ जिला शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 (फोर लेन) में जुड़ती है। जिला हरदोई और उन्नाव में इस सड़क की चौड़ाई बहुत कम है ।कुछ दिन पहले ही मल्लावां के नगर पालिका अध्यक्ष और यहां के 15 लोगों की मौत इसी सड़क पर 25 नवंबर 2024 को हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया था तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवारों को दो- दो लाख रुपये की सहायता राशि दी गई थी। मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि बिलग्राम मल्लावां स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने की स्वीकृति एवं सड़क को फोरलेन बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा की जाय। जिससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकेगी और क्षेत्रीय जनता को जान माल की सुरक्षा हो सकेगी।

(इति)

Re: Renovation of canal system in Balaghat, Seoni and areas bordering Maharashtra

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं इस सदन का ध्यान बालाघाट, सिवनी और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े क्षेत्रों जैसे बरघाट, वारासिवनी, कटंगी, लांजी और परसवाड़ा में नहरों के सुधार और उन्नयन की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इन क्षेत्रों में स्थित पुराने बाँधों की मरम्मत पिछले दस वर्षों से नहीं हो पाई है, जबकि यह प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग में पहले ही प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह परियोजना मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका जीवन वर्षा पर निर्भर है। नहरों की दयनीय स्थिति और जल आपूर्ति में आई समस्याएँ किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है, तो लाखों किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही, कांचना मंडी जलाशय में माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा मिलने से आदिवासी किसानों को भी लाभ होगा। मैं इस सदन से आग्रह करती हूँ कि इस परियोजना के तहत नहरों के उन्नयन का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि हमारे किसान बंधु संकट से उबर सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

(इति)

Re: Need to introduce flight services from Kushinagar International Airport to Mumbai, Jammu, Surat and Gulf Countries

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : हमारा कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र धार्मिक महत्व व पर्यटन के दृष्टिगत एक ऐतिहासिक स्थल है. जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। यहाँ सभी बौद्ध देशो से पर्यटको का आवागमन है , इस कारण से यह एक अंतराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते है. कुशीनगर मे अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा की शुरुआत हुई जिससे कि कुशीनगर और आसपास के जिले के निवासियों के साथ साथ दूर से आने जाने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी सुविधा मिलने लगी. परन्तु, शुरुआत से सिर्फ एक ही स्पाइसजेट की फ्लाइट चलती थी. धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वह भी अनियमित होने लगी. अक्सर यह फ्लाइट कैंसिल होने लगी जिसके कारण से यात्रियों के मन मे आशंका उत्पन्न होने लगी। मै माननीय मंत्री ज़ी से आग्रह करता हूँ कि कुशीनगर एयरपोर्ट से अन्य एयरलाइन्स कम्पनी जैसे इण्डिगो, एयर एशिया, विस्तारा की फ्लाइट की शुरुआत देश के अन्य शहरों मुंबई, जम्मू, सूरत तथा गल्फ देशो के लिए शुरुआत करने की कृपा की जाए। इस से कुशीनगर जिले के लोगो को एवं बौद्ध तीर्थ यात्रियों को देश विदेश आने जाने के लिए काफी सुविधा मिल जाएगी।

(इति)

Re: Need to ensure supply of potato and other vegetables to Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Odisha has been reeling under soaring potato prices for months, with costs climbing to Rs 30 -40 per kg. The crisis deepened recently when West Bengal, Odisha's primary potato supplier, restricted tuber transport citing rising prices in its local markets. Jharkhand is facing similar shortage of potato supply from West Bengal. The Potato growers and Traders Association of West Bengal have repeatedly objected to the highhandedness of that state's officials who are stopping transport of potatoes at their state borders. This goes against Article 301 of our Constitution which guarantees freedom of trade and commerce throughout India. I urge upon the Government to intervene and ensure free flow of vegetables, especially potatoes to Odisha.

(ends)

Re: Need to probe into the reported money laundering case in Nashik Merchant Co-operative Bank (NAMCO Bank) in Malegon, Maharashtra

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : मैं नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (NAMCO बैंक), मालेगांव शाखा में हुए अत्यंत गंभीर और चिंताजनक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हाल ही में हुई जांच में देशभर के 21 राज्यों में फैले एक व्यापक अभियान के तहत ₹114 करोड़ से अधिक की फाइनेंसियल फ्रॉड का खुलासा हुआ है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि इस फ्रॉड के लिए कई शेल कंपनियां और व्यवसायिक संस्थाएं बनाई गई थीं। ये अवैध धन कोल्हापुर, मुंबई और पुणे के खातों से भेजा जा रहा था। यह विषय अत्यंत गंभीर है। इस पैमाने की फाइनेंसियल फ्रॉड सार्वजनिक संस्थानों में लोगों के विश्वास को कम करती है। आपके माध्यम से, मैं मांग करती हूं कि सरकार से इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT), भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB), और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से कार्रवाई की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध करती हूं। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि हमारे संस्थानों की अखंडता की रक्षा के लिए और जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। (इति)

Re: Status of sovereign Gold Bond Scheme

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मेरा आपके माध्यम से सदन का ध्यान साल 2005 में शुरु की गई सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य खुदरा निवेशकों को भौतिक सोने से कागजी सोने की ओर आकर्षित करना था, जिससे देश में सोने के आयात को कम किया जा सके और लोगों को एक सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ साल थी, जिसमें पाँच साल के बाद आंशिक मोचन की सुविधा दी गई थी। शुरुआत में ब्याज दर 2.7% थी, जिसे बाद में घटाकर 2.5% कर दिया गया।

हालांकि, हाल के दिनों में ऐसी खबरे सुनने में आ रही हैं कि सरकार इस योजना को बंद करने की संभावना पर विचार कर रही है। यह कदम न केवल निवेशकों के विश्वास को ठेस पहुँचा सकता है. बल्कि सोने के आयात में वृद्धि का कारण भी बन सकता है। अतः मैं सरकार से यह स्यष्ट करने का अनुरोध करता हूँ कि क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हाँ, तो इसके पीछे के कारण क्या है? साथ ही, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार दवारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं?

(इति)

Re: Need to increase the Minimum Support Price (MSP) on wheat

DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB): This year for the first time paddy procurement has been completely de-railed. It's unfortunate that I met the Union Minister of Consumer Affairs, food and public distribution in July and told him that you need to create space for fresh stock or you will have problems. I met the Minister of Chemical and Fertilisers and told him in August that Punjab has very low DAP stocks and was promised that there would be no shortage. I am surprised that no proactive step is being taken to ensure smooth procurement of DAP. The shortage has hurt everyone involved from farmers to arthiyas to labourers to the millers. Farmers and our labourers deserve our respect and we need to solve their issues instead of blaming them for everything. Given the lower yield and lower earnings this season, Government of India should increase the wheat MSP significantly by Rs.400-500.

(ends)

Re: Need to address health issues of Beedi workers in Tirunelveli Parliamentary Constituency and enhance their pension

SHRI ROBERT BRUCE C. (TIRUNELVELI): There are more than 6 lakh beedi workers in Palayamkottai, Melapalayam, Mukkudal, Alangulam, Ambasamudram, Koodankulam and Tenkasi Districts of Tirunelveli Parliamentary Constituency. The people in the villages of Tirunelveli and Tenkasi Districts are involved in rolling beedies and therefore they suffer from occupation related health issues continuously. Now they are provided with only Rs.800/- per month as pension. It is very low and a family cannot live with a meagre sum of Rs.800/-. The pension has to be increased to Rs.6000/- per month so that they can live their life smoothly. Also, the Hospital for Beedi Workers in Mukkudal, Tirunelveli previously used to function for 24 hours, but now functioning only for Out Patients which is causing huge inconveniences to the people. I call upon the Government to take cognizance of the same and make arrangements to rectify the issues at the Beedi Workers Hospital and appoint new Nurses through the Union Public Service Commission for 24 hours operation of the hospital and to increase the pension of beedi workers from Rs.800/- to Rs.6000/- per month so as to live their life peacefully and smoothly.

(ends)

Re: Need to set up branches of Nationalised Banks and install sufficient ATMs in rural areas of Mavelikkara Parliamentary Constituency

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I wish to raise an important matter concerning the financial inclusion and economic well-being of rural areas in my constituency, Mavelikkara. Despite advancements in banking outreach, several rural regions such as Changanassery, Kuttanad, Chengannur, Mavelikkara, Kunnathoor, Kottarakkara, and Pathanapuram face a severe shortage of nationalized banking branches and ATM facilities. The lack of adequate banking infrastructure is a major impediment for farmers, small traders, senior citizens, and marginalized communities, who are unable to access essential financial services, government schemes, and cashless transaction facilities. This has led to increased travel burdens and financial insecurity among rural populations. I urge the Hon'ble Minister of Finance to take immediate steps to address this critical issue by sanctioning new branches of nationalized banks and ensuring sufficient ATM installations in these areas. Such initiatives will bolster financial inclusion, promote economic stability, and improve the standard of living for the people in these regions. I request the government's urgent intervention to resolve this long-standing issue. (ends)

Re: Need for appointment of teachers in Kendriya Vidyalayas and Jawahar Navodaya Vidyalayas on permanent basis

श्री राजीव राय (घोसी) : मैं आपका ध्यान केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज हमारे केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के कई पद लंबे समय से रिक्त हैं। इस स्थिति के कारण इन प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते हमारे विद्यार्थियों को वह उचित मार्गदर्शन और समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए आवश्यक है। इसका सीधा असर हमारे बच्चों की शिक्षा के स्तर पर पड़ रहा है। वर्तमान में सरकार ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन, इस व्यवस्था में भी कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। प्रधानाचार्य अक्सर अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। किंतु जब प्रधानाचार्य का स्थानांतरण होता है, तो नए प्रधानाचार्य अपनी पसंद के नए शिक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं। इससे विद्यालय में शिक्षकों का स्थायित्व नहीं बन पाता और छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर शीघ्रता से कदम उठाए जाएं और केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, जो कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। (इति)

Re: Need to start construction of the proposed Varanasi-Ajamgarh-Gorakhpur new railway line and also construct over-bridge in the vicinity of Majhwa Railway Station

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : मैं आपके माध्यम से वाराणसी-आजमगढ़ गोरखपुर रेल लाइन परियोजना व 19/सी पर भीमगांव ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

I. वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर को एक नई रेल लाइन के माध्यम से जोड़ने की परियोजना में थोड़ी ही प्रगति देखी गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर और वाराणसी के बीच 200 किमी की रेल लाइन प्रस्तावित है, जो आजमगढ़ से होकर गुजरेगी। नवीनतम अपडेट के अनुसार, लोकसभा सांसदों से व्यापक समर्थन मिला है, जिन्होंने इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना है। परियोजना के वास्तविक निर्माण के लिए अभी तक कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। इस रेल लाइन से क्षेत्र में रेल यातायात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पात्रियों को आसान और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी, और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। चूंकि परियोजना अभी भी योजना चरण में है, इसलिए आगे चलकर वित्तीय अनुमति, विस्तारित भूमि अधिग्रहण, और वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने का कष्ट करें।

II. मझवां रेल्वे स्टेशन पर 19/सी, चिमटी, 30/3-4 की रेल्वे पटरी है जिस पर काफी हद तक यात्री हैं। इसमें स्कूल, कालेज, अस्पताल, डाकघर, बैंक आदि सार्वजनिक सुविधाएं भी हैं। इस रेल्वे लाइन पर भीमगांव ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के लिए कार्यवाही की जाने की आवश्यक है। अतः महोदय से अनुरोध है कि आम जनता की सुविधा के दृष्टिगत 19/सी पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये की कृपा करें।

(इति)

Re: Steps taken to control inflation

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Reserve Bank of India and the Government of India have different priorities when it comes to inflation, which can lead to occasional policy tensions. RBI warns of inflation risks and threats to macroeconomic stability. Fuelling inflation in the country causing concerns about its various long-standing impact. High inflation can significantly erode purchasing power, disrupt economic stability, and ultimately lead to higher unemployment in the long run, whereas high unemployment, while causing significant hardship, can be addressed through more targeted policies to stimulate economic growth and job creation; essentially, managing inflation is seen as a key factor in maintaining overall economic health and stability. Inflation directly reduces the value of money, making goods and services more expensive for consumers. High inflation can create uncertainty in the market, discouraging investment and hindering economic growth, while high unemployment can lead to social unrest among the youths. Severe economic downturn with high unemployment, policies focused on job creation might be prioritized over inflation under control. It is absolutely important for Government and other stakeholders to work together to see how best the inflation can be controlled. I demand the Government to clarify whether it is taking any steps to control the alarming inflation. (ends)

Re: Need to bring Pollachi and Kinathukadavu Railway Stations and areas after Omalur and upto Hosur under Salem Division of the Southern Railway

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): It has been a long pending demand since the creation of Salem Division of the Southern Railway to bring Pollachi and Kinathukadavu railway Stations under Salem Division. Bringing Kinathukadavu and Pollachi Junction section under Salem division will facilitate restoration of train services to the southern districts of Tamil Nadu. There is an urgent need to expand Salem Division as the regions surrounded by Salem Division contribute highest revenues to railways as well as the development that is taking place in this region demands for it. Many representations have been submitted in this regard by various associations. Inclusion of Pollachi and Kinathukadavu Railway Stations under Salem Division will benefit railways to govern these stations more expeditiously. Similarly, area after Omalur and upto Hosur may also be brought under Salem Division as currently Salem Division is attending to matters of urgency in this section as it is more feasible although this area now comes under Bangaluru Division of South West Railway. Therefore, in the interest of the railway users and looking into the demand for more trains from Salem Division, it is urged to include Pollachi and Kinathukadavu Railway Stations and areas after Omalur and upto Hosur under Salem Division at the earliest. (ends)

Re: Need to allocate Semi-Conductor manufacturing units to be established in Tamil Nadu

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I rise to highlight the critical issue of semiconductor manufacturing in India, with a focus on Tamil Nadu's pivotal role. India is the second-largest importer of semiconductor chips globally, with imports rising by 92% in the last three years. Despite strides towards self-reliance, including approvals for three new semiconductor units in recent times, it is disappointing that none have been allocated to Southern states, which hold immense potential. Tamil Nadu leads India's electronic exports, contributing 40% of the total in 2023-24. It hosts world-class semiconductor design companies, electronics manufacturers, and R&D centers. Moreover, Tamil Nadu's over 100 academic institutions offer specialized courses in VLSI and nanotechnology, fostering a strong talent pool. Annually, 1.13 Lakh young people graduate from diploma and polytechnic institutions, while 494 ITIs provide 700 courses, aligning with semiconductor industry needs. Tamil Nadu's advanced ecosystem and skilled workforce uniquely position it to accelerate India's semiconductor goals. I urge the Union Government to allocate semiconductor manufacturing units to Tamil Nadu, leveraging its strengths to drive innovation and growth in this strategic sector.

(ends)

Re: Setting up of industries in Sheohar district, Bihar

श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) : मेरे अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर के एक महत्वपूर्ण विषय को माननीय उधोग मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूँ , शिवहर बिहार का एक छोटा जिला होने के साथ-साथ तीन ओर से सीतामंढ़ी , मुज़्जफ़रपुर और मोतीहारी से जुड़ा हुआ है और एक ओर नेपाल से जुड़ा हुआ है। शिवहर संसदीय क्षेत्र से गरीबी ओर पिछडेपन के कारण यहाँ से मजदूरों का पलायन बहुत अधिक होता है। इसका मुख्य कारण जिले में कोई भी उद्योग का न होना है। यदि वहाँ कोई सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है तो मजदूरों का पलायन तो रुकेगा ही , साथ ही वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ व्यवसाय भी होगा और राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी । अतः मंत्री महोदय जी से आग्रह है की इस विषय को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कोई उधोग स्थापित करने की कृपा करेंगे।

(इति)

Re: Livelihood and compensation to people displaced due to Sarda Sahayak Pariyojna in Uttar Pradesh

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : लंबे समय से शारदा नदी में पानी एकत्रित करने के कारण नदी तल में बालू और मिट्टी इकट्ठा होने से नदी उथली हो गई है ।वह कई धाराओं में बहकर कृषि भूमि ,आबादी व फसल लगातार नष्ट कर रही है ।बाढ़ के समय भारी तबाही मचती है। नदी कटान तेज हो जाता है। संकट के समाधान की जगह Uttar Pradesh सरकार ने शासनादेश संख्या 1417-27- सी -2-181 बाढ़ /09 दिनांक 16 .3 .2010 का हवाला देकर तटबंधों के बीच के संपूर्ण कृषि क्षेत्र व आबादी को डूब क्षेत्र/ फ्लड प्लेन जोन घोषित करके बिना मुआवजा संपूर्ण आबादी को विस्थापित करने का निर्देश जारी कर दिया है। (1) जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश स्थित शारदा सहायक सिंचाई परियोजना के लिए बने बांधों के बीच परियोजना से पहले बसे संक्रमणीय भूमिधर किसानों व खेत मजदूरो को डूब क्षेत्र/ फ्लड प्लेन जोन से विस्थापित करने के बाद उनके जीवकोपार्जन के लिए राज्य व केंद्र सरकार क्या व्यवस्था करेगी। 2- डूब क्षेत्र/ फ्लड प्लेन जोन से विस्थापित संक्रमणीय भूमिधर किसानों व खेत मजदूरो को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों से वंचित क्यों किया जा रहा है।

(इति)

Re: Need to establish an Intra Circle Hub at Shoranur Railway Mail Service office in Kerala

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): I rise to bring the attention of this house to the critical challenges posed by the proposed merger of the Shoranur Railway Mail Service (RMS) office with Speed Post processing hubs. Shoranur RMS, known as the "Gateway of Kerala" for postal goods, plays a pivotal role in sorting and dispatching postal items for 55 post offices across Malabar and neighboring regions. This merger threatens not only the efficiency of postal services but also the livelihoods of 36 departmental staff, 14 Gramin Dak Sevaks, and 22 outsourced employees, many of whom face permanent job loss. The closure of Shoranur RMS would lead to increased delivery delays, particularly for remote regions, and discontinue late-hour booking services vital for public needs. Moreover, merging distinct services like Registered Post and Speed Post without addressing disparities in postage rates compromises the trust of postal customers. Shoranur RMS office is the most important center in Kerala that handles SSLC and Plus Two exam answer paper bags. Up to 2000 exam papers are handled daily during the exam period. I urge the Government to reconsider this directive and establish an Intra Circle Hub (ICH) at Shoranur RMS to enhance service efficiency and preserve the office's operational legacy. (ends)

Re: Shortage of DAP and Urea

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : गेहूं और दलहन की बुआई के लिए आवश्यक डीएपी और यूरिया सरकारी खाद-बीज केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, किसानों की परेशानी बढ़ गई है कालाबाजारी के जरिए महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ रहा है | नैनो यूरिया का दाम 266 रूपये है जबकि खुले बाजार में इसे 350-400 रुपये की दर से बेची जा रही है | सरकारी अनुदानित दर के मुताबिक डीएपी खाद 1350 रुपये प्रति बोरी है जबकि बाजार में डीएपी 1800 से 2000 की दर से मिल रही है यूरिया खाद की कीमत नहीं बढ़ा है, लेकिन 50 किलोग्राम की जगह 45 किलोग्राम कर दिया गया | बाजार में तो सभी उर्वरक व बीज मौजूद हैं पर सरकार की तरफ से अनुदानित दर पर डीएपी खाद की व्यवस्था समय पर नहीं की गयी है। दुकानदार खाद की किल्लत का भरपूर फायदा उठा रहें है। खाद के साथ जिंक, नैनो यूरिया आदि लेना अनिवार्य कर दिया गया है नहीं तो खाद देने से साफ इनकार कर देते है। दुकानदार मिक्चर खाद को ही डीएपी बोल कर बेच रहे हैं सरकार खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित कर कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि किसान अपनी फसलों की बुआई समय पर और उचित लागत पर कर सकें। (इति)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet on Thursday, 19th December, 2024 at 11.00 am.

1409 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 19, 2024/Agrahayana 28, 1946 (Saka).